

युवा स्वस्थ दिनचर्या का पालन कर फिट रहें और प्रदेश के विकास में योगदान दें : मुख्यमंत्री

‘राज्य सरकार 92 हजार नियुक्तियां दे चुकी, इस माह भी 20 हजार युवाओं को मिलेंगी नौकरी’



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को “रन फॉर विकसित राजस्थान” में युवाओं के साथ दौड़े।

हुए अनेक पेपरलीक के प्रकरण हुए थे, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में 296 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गईं, उनमें से एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाए। राज्य सरकार ने बीते 2 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 92 हजार से अधिक

नियुक्तियां प्रदान की हैं तथा 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस माह भी लगभग 20 हजार पदों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राईजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये को ग्रांडंड ब्रेकिंग की जा चुकी है।राज्य सरकार युवाओं को कौशल

■ **पिछली कांग्रेस सरकार में पेपरलीक हुए: हमने 296 भर्ती परीक्षाएं करवाईं, इनमें से एक का भी पेपरलीक नहीं हुआ : भजनलाल शर्मा**

दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों के साथ दौड़ में हिस्सा लेकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इससे पहले भजनलाल शर्मा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पदक विजेताओं का सम्मान भी किया। इस दौरान विधायक कुलदीप, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, शासन सचिव युवा मामले एवं खेल नीरज के. पवन सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर व लायन सफारी बनी आकर्षण का केन्द्र

जयपुर। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रविवार को पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। बदलते मौसम के सुहावने मिजाज और छुट्टी के दिन के उत्साह ने पर्यटकों को प्रकृति की गोद में खींच लाया। कुल 4025 सैलानियों ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान का भ्रमण कर वन्यजीवों का नजदीक से अवलोकन किया।

इस दौरान लायन सफारी और टाइगर सफारी

■ **20 दिनों में 30 हजार से ज्यादा सैलानियों ने सिया रोमांचक अनुभव**

पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बनी रही। उप वन संरक्षक देवेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 552 पर्यटकों ने दोनों सफारियों का रोमांचक अनुभव

प्राप्त किया और शेर व बाघ की चंचल अदाओं को देख उत्साहित हुए। बाघों की गर्जना और शेरों के शाही ठाठ ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गौरतलब है कि पर्यटन सीजन में सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है यही कारण है कि विगत 20 दिनों में 30 हजार से अधिक सैलानी टाइगर व लायन सफारी का रोमांचक अनुभव उठा चुका है। उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के निर्देशन

में पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड़, रंजर शुभम शर्मा ने रविवार को सफारियों की सघन मॉनिटरिंग की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रैंज अधिकारी शुभम शर्मा की देखरेख में ट्रिज्म मैनेजमेंट टीम द्वारा सफारी संचालन और भीड़ नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की गई।

अशोक गहलोत का दावा “ 90 प्रतिशत अरावली खत्म हो जाएगी” पूरी तरह भ्रामक और असत्य : राजेन्द्र राठौड़

‘अरावली श्रृंखला के मानदंड कांग्रेसराज में लागू हुए थे, वर्ष 2003 में जिलेवार नक्शे भी मुख्यमंत्री रहते गहलोत ने जारी किए थे’

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर । भाजपा के पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह दावा पूरी तरह भ्रामक और झूठा है कि “90 प्रतिशत अरावली खत्म हो जाएगी।” अरावली पर्वतमाला जैसे गंभीर पर्यावरणीय विषय पर सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार के विरूद्ध भ्रम फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। करीब द्वाई अरब साल पुरानी, विश्व की सबसे प्राचीन 700 किमी लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर का मानदंड केवल ऊंचाई तक सीमित नहीं है। न्यायालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों, उनकी ढलानों और दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू-आकृतियां खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रखी गई हैं, चाहे उनकी ऊंचाई कुछ भी हो। यह व्यवस्था पहले से अधिक सख्त और वैज्ञानिक है।

राठौड़ ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि वास्तविक स्थिति यह है कि अरावली क्षेत्र का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा



राजेन्द्र राठौड़

अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वनों में आता है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा पूरे अरावली क्षेत्र में से केवल लगभग 2.56 प्रतिशत क्षेत्र ही सीमित, नियंत्रित और कड़े नियमों के तहत खनन के दायरे में आता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्टरि रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र का विस्तृत वैज्ञानिक मापन और सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में अरावली के

■ **अरावली सुरक्षित है, सरकार का रुख स्पष्ट है-अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और कानून का पालन सर्वोपरि रहेगा : राठौड़**

■ **राठौड़ ने कहा कि गत 18 दिसंबर को गहलोत ने “अरावली बचाओ” के नाम पर सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा और प्रोफाइल पिक्चर बदली। परंतु राहुल गांधी, खरगे, पायलट अश्वना डोटारसरा ने अपनी प्रोफाइल फोटो नहीं बदली। यह दर्शाता है कि जो दावा गहलोत कर रहे हैं, उसमें स्वयं उनकी पार्टी का समर्थन भी नहीं है।”**

नष्ट होने की बात करना अशोक गहलोत का सिर्फ भ्रम फैलाने का प्रयास है। राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, कमेटी की बातचीत में यह स्पष्ट तथ्य सामने आए कि अरावली क्षेत्र में खनन को नियंत्रित करने की औपचारिक परिभाषा केवल राजस्थान के पास थी, जो 2002 की कमेटी रिपोर्ट और रिचर्ड मर्फ (1968) के लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन पर आधारित है। इस परिभाषा के अनुसार स्थानीय ऊँचाई से 100 मीटर या उससे अधिक उठने वाली पहाड़ियों और उनकी ढलानों पर खनन प्रतिबंधित है

और राजस्थान 9 जनवरी 2006 से

इसका पालन कर रहा है। यानी तब से

ऐसी पहाड़ियों में कोई खनन पट्टा नहीं दिया गया। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह कहना कि केंद्र सरकार ने अरावली को 100 मीटर में सीमित कर दिया है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि यही मानदंड कांग्रेस शासनकाल में तय और लागू हुआ था। गत 19 अगस्त 2003 को जिलेवार नक्शे तैयार करने के निर्देश भी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते जारी किए गए थे। वर्षों तक इस परिभाषा को लागू

रखने के बाद आज इसे गलत बताया न्यायिक फैसले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं तो और क्या है ?

राठौड़ ने कहा कि गत 18 दिसंबर को अशोक गहलोत ने “अरावली बचाओ” के नाम पर सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया और अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारसरा, न कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं न कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और न ही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। यह साफ दर्शाता है कि जिस अभियान का दावा किया जा रहा है, उसमें स्वयं उनकी पार्टी का समर्थन भी उनके साथ नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब किसी मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेता भी उनके साथ खड़े न हों, तो स्पष्ट हो जाता है कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि राजनीतिक दिखावा है। अरावली जैसे संवेदनशील विषय पर प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों और वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार

ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

राठौड़ ने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कमेटी की परिभाषा लागू होने पर अरावली क्षेत्र में खनन नहीं बढ़ेगा बल्कि और अधिक सख्ती आएगी। राजस्थान के राजसमंद में 98.9 प्रतिशत, उदयपुर में 99.89 प्रतिशत, गुजरात के साबरकांठा में 89.4 प्रतिशत और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 75.07 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र खनन से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय उद्यान, इको-सैंसिटिव ज़ोन, रिजर्व एवं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में खनन पूरी तरह बंद है। वर्तमान में अरावली क्षेत्र के 3.7 जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.19 प्रतिशत (277.89 वर्ग किमी) हिस्सा ही कानूनी खनन पट्टों के अंतर्गत है जिसमें भी लगभग 90 प्रतिशत खनन राजस्थान, नौ प्रतिशत गुजरात और एक प्रतिशत हरियाणा तक सीमित है। इसलिए 90 प्रतिशत अरावली पहाड़ियों के खत्म होने की बात कानूनी और भौगोलिक रूप से पूरी तरीके से असत्य है।

राठौड़ ने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया

एलईडी वैन से गांव-गांव पहुंच रहीं सरकार की उपलब्धियां



जयपुर । वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित 2 साल : नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जयपुर जिले में विकास रथों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विकास रथ (एलईडी वैन) द्वारा जिले की विभिन्न विधानसभाओं के गांव-गांव तक पहुंचकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जा रही है।

इसी कड़ी में रविवार को जिले की पांच विधानसभाओं के विभिन्न ग्रामों में एलईडी वैन के माध्यम से विकास रथों ने भ्रमण कर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। एलईडी स्क्रीन पर आँडियो-विजुअल प्रस्तुतियों के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बीते दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, किसानों के हित में लिए

■ **विकास रथ बने ग्रामीणों के आकर्षण का केन्द्र, योजनाओं की जानकारी से हो रहे रुबरू**

गए निर्णयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी एवं रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया।

उल्लेखनीय है कि जयपुर जिले की सभी 17 विधानसभाओं में विकास रथों के माध्यम से यह प्रचार-प्रसार अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकार की विकास यात्रा को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाना, पारदर्शिता के साथ उपलब्धियों से अवगत कराना तथा आमजन को सरकार की योजनाओं से सीधे जोड़ना है।

यह जनसंपर्क अभियान न केवल सरकार की जनकल्याणकारी सोच को सशक्त रूप से प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि आमजन में विश्वास, सहभागिता एवं जागरूकता को भी सुदृढ़ कर रहा है।

3 साल से फरार साइबर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा

जयपुर। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने तीन साल से फरार चल रहे दस हजार रुपए के इनामी साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बिजली बिल अपडेट कराने के नाम पर बुजुर्ग से चार लाख रुपए से अधिक की ठगी कर फरार हो गया था। फिलाहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व सजीव नैन ने बताया कि जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने तीन साल से फरार चल रहे दस हजार रुपए के इनामी साइबर ठग कुलदीप (28) निवासी आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा) को दबोच लिया। जिसे पुलिस टीम ने हरियाणा एसटीएफ के सहयोग से हरियाणा से दबोचा है। थानाधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर 2022 को मालवीय नगर निवासी 77 वर्षीय श्याम सुंदर वैष्णव ने रिपोर्ट दी थी कि 13 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर कॉल कर खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताने वाले व्यक्ति ने बिजली बिल अपडेट न होने की बात कही। इसके बाद आरोपी ने एक एप डाउनलोड करवाकर नेट बैंकिंग के जरिए खाते से 4 लाख 55 रुपए से अधिक की राशि निकाल ली। साथ ही पॉडित के पेटीएम वॉलेट से भी रकम ट्रांसफर कर ली गई। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंगल (आरपीएस) और सहायक पुलिस आयुक्त विनोद शर्मा (आरपीएस) के निर्देशन में जवाहर सर्किल थानाधिकारी आशुतोष सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर आरोपी लगातार ठिकाने पर दबिश दी।

राजस्थान में परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना मजबूत कर रही सरकार

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं प्रभावी नीतियों के फलस्वरूप राजस्थान में परिवहन तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना के विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य सरकार द्वारा माल परिवहन लागत में कमी लाने एवं औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गत 2 वर्षों में किए गए प्रयास अब मूर्त रूप ले रहे है।

माल परिवहन को और अधिक सुलभ, त्वरित एवं किफायती बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रमुख धुरी माने जाने वाले पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के प्रदेश से गुजरने वाले खंड में सभी फ्रेट कॉरिडोर स्टेशनों को ऑल-वेयर टू-लेन सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 12 नवीन स्टेशनों तक कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए लगभग 112 करोड़ रुपये की लागत से 59 किलोमीटर लंबी टू-लेन सड़कों के निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। इनमें से चार स्टेशनों- किशनगढ़, मारवाड़ जंक्शन, केशवगंज एवं बनास स्टेशनों तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

■ **पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चार स्टेशन टू-लेन सड़कों से जुड़े, 8 स्टेशनों का काम शीघ्र होगा पूरा**

■ **112 करोड़ रुपये की लागत से 59 किलोमीटर लंबी टू-लेन सड़कों का निर्माण**

■ **564 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर पर 18 नवीन फ्रेट स्टेशन विकसित कर रही है राज्य सरकार**

अन्य आठ स्टेशनों, श्रीमाधोपुर, सराधना, हरिपुर, चंडावल, जवाली, विरोलिया, साखुन एवं स्वरूपगंज स्टेशनों की भी टू-लेन सड़कों से जोड़ने का कार्य जारी है। इन सड़कों के निर्माण से उद्योगों को कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों के परिवहन में सुगमता मिलेगी। साथ ही लागत में भी कमी आएगी।

लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि होने के कारण औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा तथा रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगे। फ्रेट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ बनाने के लिए बयाल डीएफसीसी टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से जोड़ने के लिए 95 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही मुख्य जिला सड़क-81 पर बागावास बाईपास के निर्माण के लिए 10 करोड़

रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। यहां भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

इसके अतिरिक्त मंडा रीको औद्योगिक क्षेत्र को लालासर (एमडीआर-81) से जोड़ने के लिए 9 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए जा रहे 1504 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में से लगभग 564 किलोमीटर का महत्वपूर्ण खंड राजस्थान से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर 18 नवीन फ्रेट स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से 12 स्टेशन पूर्व में समुचित सड़क संविधा से वंचित थे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद इन सभी स्टेशनों को ऑल वेयर रोड से जोड़ने का काम प्रगति पर है।

युवक से मोबाइल छीन भागे बदमाश

जयपुर। गांधी नगर इलाके में बाइक सवार बदमाश पैदल फोन पर बात करते जा रहे युवक के हाथ पर झपट्टा मार आईफोन छीनकर फरार हो गए। अचानक हुई वारदात से पीड़ित घबरा गया और बाइक के नंबर नहीं देख सका। पीड़ित ने थाने पहुंच घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए आसपास नाकाबंदी भी की। लेकिन पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी। पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ लुट का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश शुरु कर दी है। हेड कॉन्स्टेबल भरतलाल ने बताया कि रीताश सिंह (33) डीग,कुम्हेर निवासी

शनिवार रात करीब साढ़े 10 बजे नारायण सिंह सर्किल से नगर निगम कार्यालय की तरफ पैदल मोबाइल फोन पर बात करता हुआ जा रहा था। इसी दौरान सुबोध कॉलेज के गेट के पास रॉंग साइड से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा और आईफोन -13 प्रो छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने बाइक सवार बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन बाइक सवार बदमाश तेज रफ्तार में बाइक चलाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ लुट का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

“सियाचिन” में भारतीय सेना की वीरगाथा मंच पर जीवंत

जयपुर। रंगमंच की रंगत, कला एवं संस्कृति के सौंदर्य से सराबोर करने वाले 14वें जयरंगम (जयपुर रंग महोत्सव) का रविवार को समापन हुआ। फेस्टिवल में कला प्रियियों ने न केवल बेहतरीन नाटक देखे बल्कि संगीत और संस्कृति से भी रुबरू हुए। अंतिम दिन जयपुर वॉल्ड सिटी में हेरिटेज वॉक के साथ दिन की शुरुआत हुई।

कृष्णायन में श्रीनिवास बिसेट्टी के नाटक ‘वेटिंग फॉर नसीर’ का मंचन हुआ। वहीं प्रियाक्षी अग्रवाल द्वारा शोध-आधारित प्रस्तुति ‘नंगा कपड़ा’ महिलाओं की सुखर आवाज बनकर उभरी

रंगायन में मकरंद देशपांडे का नाटक ‘सियाचिन’ में भारतीय सेना की वीरगाथा को मंच पर जीवंत किया गया। सोहन नायर द्वारा निर्देशित नाटक ‘गोल्डन जुबली’ के मनोरंजक मंचन के साथ जयरंगम-2025 का भव्य समापन हुआ। फेस्टिवल डायरेक्टर मन गेरा ने बताया कि जयरंगम में इस वर्ष स्पाॅटलाइट के तहत महिला निर्देशकों के नाटकों को मंच प्रदान किया, आगेले सीजन में नए नाटकों और बेहतरीन प्रस्तुतियों के साथ जयरंगम समाज के हर वर्ग की सशक्त आवाज बनकर सामने आएगा। ये भारतीय सेना के जवानों का जज्बा है जो न रेगिस्तान में

■ **रंगमंच, कला और संस्कृति के रंगों से रुबरू कराकर विदा हुआ जयरंगम**

सुरज की आग से जलता है ना ही सियाचिन में बर्फाली हवाओं से जमता है। रंगायन के मंच पर मकरंद देशपांडे के निर्देशन में खेले गए सियाचिन नाटक में बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर बनी भारत की सरحد को सुरक्षा कर रहे सैनिकों के बलिदान को बर्ण किया गया। समुद्र तल से 21 हजार फीट ऊंची सियाचिन की पोस्ट पर चार जवान तैनात है। यह पोस्ट तुफान का शिकार हो जाती है। इनमें से एक जवान की जिंदगी इसकी भेंट चढ़ जाती है। तीनों असहनीय परिस्थितियों में भी पोस्ट पर डटे रहते हैं और सहायता का इंतजार करते हैं। हालात बड़े से बदतर होते जाते हैं। तीनों जवान अंतिम श्वास तक अपनी पोस्ट पर डटे रहते हैं क्योंकि फर्ज उन्हें याद दिलाता है कि देश की एक इंच जमीन पर भी दुश्मन की नजर नहीं पड़नी चाहिए। आतिश्य रावल, जगन कपूर, निकेतन शर्मा, चित्रांशु, जतिन सरीन, रोहित मेहरा, श्रुति, वैभव जाधव, अक्षय खैर, मोहित कुमार सोलंकी और अभिषेक मिश्रा ने भूमिका निभाई।

अलमाइटी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव

जयपुर । सदियों पुराने वैदिक विज्ञानों को आधुनिक युग की चेतना से जोड़ते हुए रविवार को जयपुर में ऐतिहासिक अध्यय जुड़ा, जब अलमाइटी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव (एआईसी) सीजन-2 का आगाज हुआ। अलमाइटी इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल वास्तु अकादमी के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे। इस राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव में देशभर से प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, आध्यात्मिक गुरु, ओकल्ट साईंस एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रालयन के साथ डॉ. रोशनी टाक, स्वामी अमित देव, अनूपम जॉली, पं. अशोक दीक्षित, डॉ. एके दुबे, पद्मेश कानुपुर, अजय भाम्नी, स्वामी पद्मनाभ महाराज, पं. ज्योति शर्मा, डॉ. विनोद शर्मा, पं. सतीश शर्मा और डॉ. मेधा शर्मा द्वारा किया गया। एसाईएसी की संस्थापक डॉ. मेधा शर्मा और प्रदीपन पं. सतीश शर्मा ने आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। महामंडलेस्वर आचार्य स्वामी पद्मनाभदेवाचार्य ने आध्यात्मिक संबोधन से जनसमूह को आत्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत किया। मंडिटेशन मंत्र सत्र में निर्मला सेवानो ने वातावरण को ऊर्जावान बनाया। महिला ज्योतिष आंरा सत्र का संचालन करते हुए आरजे देवांगना ने आज की महिला के बारे में डॉ. मेधा शर्मा, पं. ज्योति शर्मा, डॉ. रोशनी टाक और पूजा शर्मा से बात की, जिसमें ये निष्कर्ष निकला कि आज की नारी अक्सर ज्योतिषाचार्यों से परिवार के बारे में पूछती है।

■ **अरावली पर्वतमाला राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, दिल्ली सहित आठे हिंदुस्तान को रेगिस्तान बनने से बचाने, वर्षा, हरियाली, स्वच्छ हवा और पर्यावरण संतुलन रखने में भूमिका निभाती है : प्रताप सिंह**

झूठ है। भाजपा सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के कारण ही यह स्थिति बनी है और फैसला तुरंत बदला जाना चाहिए।

पदयात्रा के दौरान लोग हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अरावली बचाओ-जीवन बचाओ के नारे लगाते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंचे। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने फूल बरसाकर पदयात्रियों का स्वागत किया। सत्याग्रह में बड़ी संख्या में आमजन और सामाजिक संगठन शामिल हुए।



“अरावली बचाओ” के नारों के साथ सैकड़ों लोगों ने रविवार को जयपुर में रैली निकाली।

होने का खतरा पैदा हो गया। खाचरियावास ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हैं और केंद्र सरकार को अपना रुख बदलते हुए अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। अन्यथा संघर्ष और टकराव होगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत लगा दी जाए, अरावली में किसी भी कीमत पर खनन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान,

“ अरावली बचाओ-जीवन बचाओ” सत्याग्रह शुरू

हजारों लोगों ने अंबेडकर सर्किल तक पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व निकाली पदयात्रा

जयपुर (कासं)। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह

खाचरियावास के नेतृत्व में रविवार को “अरावली बचाओ-जीवन बचाओ” सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इस दौरान खाचरियावास हाउस से अंबेडकर सर्किल तक हजारों लोगों ने पदयात्रा निकाली और सचिवालय के पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे 45 मिनट का मौन सत्याग्रह कर आंदोलन का आगाज किया।

खाचरियावास ने भाजपा सरकार पर अरावली पर्वतमाला को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए पूरी तरह केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ झूठ के जनरेटर हैं और सरकार जनता को गुमराह कर रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की, जिसने उद्योगपतियों से सांठगांठ कर गलत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली नहीं मानने की सिफारिश की गई, जिससे 90 प्रतिशत अरावली पहाड़ियों खत्म